

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0)-7

देहरादून: दिनांक 09 फरवरी, 2010

विषय:-राज्य सरकार के कर्मियों के लिए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किया जाना।

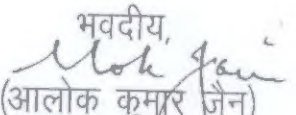
महोदय,

वेतन विसंगति समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए शासनादेश संख्या-75 XXVII(7) ए0सी0पी0/2009, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा लागू की गयी सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्ययन/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम को अतिक्रमित करते हुए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अनुरूप सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्ययन योजना (ACP) संलग्न विस्तृत दिशानिर्देश के अनुरूप लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त योजना दिनांक 1-1-2006 के पूर्व के वेतनमान रु0 7500-12000 पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड पे रु0 4800 तक के पदधारकों के लिए दिनांक 1-9-2008 से तथा वेतनमान रु0 8000-13500 पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड पे रु0 5400 तथा उससे ऊपर के वेतनमान के पदधारकों के लिए दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी होगी।

3- योजना का विस्तृत स्वरूप एवं शर्तें संलग्न है।

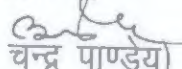
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,  
  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव

संख्या-444(1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 3-महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
- 4-प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
- 5-सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
- 6-स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
- 7-समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8-उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9-निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
- 10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव।



शानादेश संख्या:444/xxvii(7)ए0सी0पी0/2010 का संलग्नक

1. सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन की उक्त योजना के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर अनुमन्य होंगे। उक्त योजना के अन्तर्गत कार्मिक के द्वारा अविरल रूप से एक ही ग्रेड पे पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही देय होगा।
2. उक्त योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2009 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 में दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में पदधारक को प्राप्त हो रहे ग्रेड पे से अगला ग्रेड पे अनुमन्य होगा। इस प्रकार उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ग्रेड पे पद धारक के नियमित पदोन्नति के पद के ग्रेड पे से किन्हीं मामलों में भिन्न भी हो सकता है और ऐसे मामलों में संगत संवर्ग में सेवानियमावली के अनुसार अगले पदोन्नति के पद के अनुरूप ग्रेड पे संबंधित कार्मिक के नियमित पदोन्नति पर ही देय होगा।
3. उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ के पे बैंड-4 में उच्चतम ग्रेड पे रू0 10,000 तक अनुमन्य होगा।
4. पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण का जो लाभ प्राप्त होता है वही वित्तीय लाभ उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य करते समय देय होगा। इस प्रकार स्तरोन्नयन के पूर्व कार्मिक को उसके वेतन बैंड में दिये जा रहे वेतन तथा ग्रेड पे के योग पर 3 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी। उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे ग्रेड पे के पद पर नियमित पदोन्नति की स्थिति में किसी प्रकार का वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। यदि उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ग्रेड पे के सापेक्ष अगली पदोन्नति उच्च ग्रेड पे वाले पद पर होती है तब ऐसी स्थिति में कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और केवल ग्रेड पे में अन्तर की धनराशि ही अनुमन्य होगी। उदाहरणार्थ:- यदि एक राज्य सरकार के कार्मिक की पे- बैंड-1 में रू0 1900 के ग्रेड पे के पद पर सीधी भर्ती होती है और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उसे कोई पदोन्नति अनुमन्य नहीं होती है तो उसे उक्त योजना के अन्तर्गत उसके पद से उच्च ग्रेड-पे रू0 2000 का वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा और उसको प्राप्त हो रहे वेतन में एक वेतन वृद्धि तथा ग्रेड-पे के अन्तर (रू0 100) अनुमन्य होगा। वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत उच्चीकरण का लाभ उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य होने के बाद यदि उक्त कार्मिक का अपन संवर्ग में पदोन्नति के प्रक्रम में रू0 2400 के ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति

✓



होती है तो नियमित पदोन्नति के समय उसे मात्र ग्रेड-पे का अन्तर(रू02400-2000=400) रू0 400 अनुमन्य होगा और इस स्तर पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5. पूर्व में अनुमन्य पदोन्नति या समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वेतनमान के उच्चीकरण के फलस्वरूप यदि वेतन समिति के द्वारा दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में 2-3 वेतनमान एक ही वेतनमान/उच्चीकरण के फलस्वरूप एक ही वेतनमान में संविलियन हो गये हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त योजना के अन्तर्गत देय सुविधा के लिए उक्त वेतनमानों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। उदाहरणार्थ:- किसी संवर्ग में बढ़ते क्रम में वेतनमान के पुनरीक्षण के पूर्व वेतनमान क्रमशः रू0 5000-8000, रू0 5500-9000 एवं रू0 6500-10500 हैं:-

(क) एक सरकारी कर्मचारी जिसकी पूर्व में भर्ती अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5000-8000 में होने के बाद उसे दिनांक 1-1-2006 के पूर्व 25 वर्ष बाद भी पदोन्नति नहीं हुयी है, इस प्रकरण में दिनांक 1-1-2006 को उन्हें दिनांक 1-1-2006 तक उक्त योजना के अन्तर्गत दो वित्तीय स्तरोंन्नयन अगले दो वेतनमान के प्राप्त हो जाने चाहिये थे। उदाहरणार्थ:- रू0 5500-9000 एवं रू0 6500-10500 के अपुनरीक्षित वेतनमान में देय होने चाहिये थे।

(ख) दूसरा सरकारी कर्मचारी उसी संवर्ग में पूर्व के रू0 5000-8000 के अपुनरीक्षित वेतनमान में भर्ती हो कर उसे 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक उसे अगले दो वेतनमान क्रमशः रू0 5500-9000 एवं रू0 6500-10500 के वेतनमान के पदों पर दो पदोन्नतियों प्राप्त हो गयी है।

उक्त 'क' एवं 'ख' के प्रकरणों में कार्मिक को दिनांक 1-1-2006 के पूर्व रू0 5500-9000 एवं रू0 6500-10500 के वेतनमान में प्राप्त हुयी पदोन्नतियों/समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्राप्त लाभ को दिनांक 1-1-2006 से उक्त वेतनमानों के संविलियन के फलस्वरूप स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। दोनों कार्मिकों को पे-बैण्ड-2 में रू0 4200 का ग्रेड-पे अनुमन्य होगा। उक्त योजना के लागू होने के बाद, उक्त 'क' एवं 'ख' के दोनों कार्मिकों को पे-बैण्ड-2 में उनको प्राप्त हो रहे ग्रेड-पे के अगले दो ग्रेड-पे क्रमशः रू0 4600 एवं रू0 4800 अनुमन्य होंगे।

✓

6. जिन कर्मचारियों को पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2006 के पूर्व वित्तीय स्तरान्तरण प्राप्त हो चुका है, उनका वेतन निर्धारण उनको पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त हो गये वेतनमान के अनुसार ही किया जाएगा।

(1) यदि समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2006 से दिनांक 31-8-2008 तक किसी कार्मिक को समयमान वेतनमान प्राप्त हुआ है तो उसे पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु निम्नलिखित विकल्प हैं:-

(क) 1-1-2006 से पूर्व के वेतनमान में दिनांक 1-1-2006 से वेतन निर्धारण या

(ख) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत जिस तिथि से वेतनमान का उच्चीकरण हुआ है उस तिथि से वेतन निर्धारण। उक्त बिन्दु-‘ख’ के अनुसार विकल्प देने पर उसे एरियर का भुगतान केवल उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने अर्थात् समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वेतनमान उच्चीकरण की तिथि से ही देय होगा।

(2) पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अपने संवर्ग के अनुसार अगले वेतनमान में वित्तीय स्तरान्तरण प्राप्त हो गया हो, लेकिन छठवें वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने के बाद संवर्ग में अगला उच्च वेतनमान का उच्चीकरण उच्च ग्रेड-पे पर हो गया है ऐसे कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण उक्त उच्च ग्रेड-पे के अनुसार किया जाएगा।

7. किसी कार्मिक की उक्त वित्तीय स्तरान्तरण की योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्तरान्तरण/पदोन्नति होने पर कार्मिक को यह विकल्प प्राप्त है कि वह पदोन्नति/उच्चीकरण की तिथि या दिनांक 1-1-2006 से वेतन निर्धारण का विकल्प दे सकता है।

8. चयन के नियमों के अन्तर्गत यदि पदोन्नति के सोपान में एक ही ग्रेड-पे वाले पद पर पदोन्नति होती है तो उसे उक्त योजना के अन्तर्गत गणना में लिया जाएगा।

9. ‘नियमित सेवा’:- उक्त योजना के अन्तर्गत नियमित सेवा का तात्पर्य नियमित सेवा का प्रारम्भ, सीधी भर्ती या संविलियन या पुन्योजन के आधार पर नियमित रूप से सीधी नियुक्ति के पद पर भर्ती से है। तदर्थ/संविदा के

✓



आधार पर नियुक्ति के बाद नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण की अवधि को नियमित सेवा के रूप में गणना में नहीं लिया जाएगा। लेकिन नये विभाग में नियमित नियुक्ति के पूर्व राज्य सरकार तथा भारत सरकार के अधीन उसी ग्रेड वेतन पर नियमित निरंतर संतोषजनक सेवा को उक्त योजना के अन्तर्गत नियमित सेवा के रूप में गणना में लिया जाएगा, परन्तु ऐसे प्रकरणों पर उक्त योजना का लाभ नये पद पर परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा। राज्य सरकार में आने से पूर्व सांविधिक संस्थान/स्वायत्तशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम/निगम में की गई सेवा को उक्त लाभ हेतु नियमित सेवा में गणना में नहीं लिया जाएगा।

10. सक्षम अधिकारी की नियमित रूप से स्वीकृत प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा अन्य अवकाश में व्यतीत की गई अवधि को नियमित सेवा में की गई सेवा में गणना में लिया जाएगा। उक्त योजना वर्कचार्ज कर्मचारियों पर तभी लागू होगी जब उनकी सेवा शर्तें नियमित अधिष्ठान के पदधारकों के समान हों।

11. वर्तमान में प्रचलित समयबद्ध प्रोन्नति की योजनाएँ जिनमें in-situ पदोन्नति योजना, वाहन चालक स्टाफिंग पैटर्न या वर्ग विशेष के लिए लागू अन्य पदोन्नति की योजना तब तक लागू रहेगी जब तक सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको बनाये रखने का सम्यक् रूप से निर्णय लिया जाता है अन्यथा उन पर उक्त योजना लागू होगी। लेकिन उक्त योजनाएं इस योजना के साथ-साथ लागू नहीं रहेगी।

12. उक्त योजना केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होगी और यह मंत्रालय/विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में स्वायत्तशासी निकाय/सांविधिक निकायों पर स्वतः ही लागू नहीं होगी। उक्त योजना को ऐसी निकायों में लागू किये जाने से पूर्व इससे पड़ने वाले वित्तीय उपाशय को ध्यान में रखते हुए संबंधित निकाय के प्रशासकीय इकाई/निदेशक मण्डल तथा संबंधित विभाग के द्वारा निर्णय लेकर वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।

13. उक्त योजना के अन्तर्गत यदि कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होने के कारण वह 10 वर्ष के अन्दर वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत एक ग्रेड-पे के लिए अर्ह नहीं होता है तो इसका परिणामी असर आगामी वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा और प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के बाद उक्त देय

✓

आगामी स्तरोन्नयन भी उक्त बिलम्बित अवधि के लिए अग्रेशित किया जाएगा।

14. उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के उपरान्त कार्मिक के पदनाम, वर्गीकरण एवं प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वित्तीय एवं अन्य प्रकार के लाभ जो कार्मिक के आहरित वेतन पर निर्भर करते हैं जैसे- भवन निर्माण अग्रिम, सरकारी आवास आवंटन आदि के लिए इसे गणना में लिया जाएगा।

15. पी0बी-1 के अन्तर्गत ग्रेड-पे के क्रम में वित्तीय स्तरोन्नयन कार्मिक की स्वस्थता(fitness) के आधार पर नॉन फक्शनल बेसिस पर तथा उक्त के बाद रू0 6600 तक के ग्रेड पे में 'अच्छा' (good) तथा रू0 7600 अथवा इससे उच्च के ग्रेड-पे पर 'बहुत अच्छा'(very good) का मापदण्ड निर्धारित किया जाएगा

16. उक्त योजना की अनुमन्यता हेतु अनुशासनात्मक/दण्डात्मक प्रक्रियां पदोन्नति के राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों से ही शासित होंगी।

17. उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ केवल वैयक्तिक रूप से अगला ग्रेड-पे/वित्तीय लाभ के लिए ही होगा और इसका आशय कार्मिक की वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति से नहीं है इसलिए इस योजना में आरक्षण के नियम/रोस्टर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त लाभ समान रूप से समस्त अर्ह अनु0जाति/जनजाति के कार्मिकों के लिए भी है।लेकिन कार्मिक की नियमित पदोन्नति के समय समस्त आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा, उक्त कारण से ही यह आवश्यक नहीं होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी जो वित्तीय स्तरोन्नयन के मामलों पर विचार करेगी, में अनु0जाति/जनजाति के संबंध सदस्य के रूप में हो।

18. उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन कार्मिक की वैयक्तिक स्थिति होगी और इसका कार्मिक की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं होगा। वरिष्ठ कार्मिकों के लिए इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, कि कनिष्ठ कार्मिक को उससे उच्च वेतन/ग्रेड-पे उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य हो गया है।

✓



19. सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य किये गये वेतन बैंड में आहरित वेतन तथा ग्रेड-पे को जोड़ते हुए समस्त परिणामी लाभ अनुमन्य होंगे।
20. समूह 'क' के वे राजकीय कार्मिक जो अब तक पूर्व योजना से आच्छादित नहीं हो सके हैं और वे अब तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के लिए सीधे अर्ह हो गये हैं क्योंकि उनके द्वारा 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली गयी है, उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में क्रमशः अगले तीन उच्च ग्रेड-पे में 3 प्रतिशत की वृद्धि देते हुए प्रत्येक स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। जो कार्मिक द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के लिए अर्ह है उसका वेतन भी उक्तवत निर्धारित किया जाएगा।
21. यदि कोई कार्मिक अपने संगठन में सरप्लस घोषित होने के बाद उसी वेतनमान या नीचे के वेतनमान में नये संगठन में नियुक्त होता है तो पूर्व संगठन में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा को नये संगठन में की जा रही नियमित सेवा में उक्त योजना के लाभ हेतु गणना में लिया जाएगा। यदि कोई कार्मिक पदोन्नत होने पर/पूर्व में अनुमन्य समयमान वेतनमान से एक-पक्षीय रूप से निम्न पद या निम्न वेतनमान के पद पर स्थानान्तरण का अनुरोध करता है तो वह उक्त योजना के अन्तर्गत 20 तथा 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर, जैसा भी प्रकरण हो, नये संगठन में प्रथम पद पर नियुक्ति की तिथि से क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन अनुमन्य होगा।
22. यदि कार्मिक को वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता होने के पूर्व नियमित पदोन्नति अनुमन्य होने पर कार्मिक के द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऐसे कार्मिक को कोई वित्तीय स्तरोंन्नयन का लाभ इस कारण अनुमन्य नहीं होगा क्योंकि उसका स्टेगनेशन अवसर की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो रहा है। यदि स्टेगनेशन के कारण वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमति दी जाती है और कार्मिक बाद में पदोन्नति लेने से मना करता है तो यह वित्तीय स्तरोंन्नयन लेने का आधार नहीं बनेगा लेकिन ऐसी स्थिति में वह आगामी वित्तीय स्तरोंन्नयन के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक वह पदोन्नति के लिए सहमत नहीं होता है तथा द्वितीय तथा

✓



अगला वित्तीय स्तरान्तरण असहमति की अवधि तक के लिए डिफर कर दिया जाएगा।

23. अन्य प्रकरणों के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा ऐसे कार्मिकों के प्रकरण पर भी विचार किया जाएगा जो उच्च पद तदर्थ आधार पर धारित किये हुए हैं। ऐसे पदधारकों को वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अपने निम्न वेतनमान के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित होने या तदर्थ रूप से धारित पद के वेतन से अधिक लाभकारी होने पर अनुमन्य होगा।

24. उक्त योजना का लाभ की अनुमन्यता हेतु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक को अपने पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तन आवश्यक नहीं होगा, वरन् उसके द्वारा इस आशय का नया विकल्प कि वह धारित पद के पे-बैंड तथा ग्रेड-पे के अनुरूप वेतन आहरित करेगा या उक्त योजना के अन्तर्गत वेतन तथा ग्रेड-पे के अनुरूप, जो भी लाभप्रद हो, दे सकता है।

25. उदाहरण:-

क-(1) यदि पे बैंड-1 में ग्रेड-पे-रू01900 में कार्यरत कनिष्ठ सहायक का उसके पे-बैंड में प्रथम पदोन्नति प्रवर सहायक ग्रेड पे-रू02400 में 8 वर्ष की सेवा पर हो जाती है और वह उसी ग्रेड-पे पर बिना पदोन्नति के 10 वर्ष तक कार्यरत रहता है तब वह उक्त पे-बैंड में उक्त योजना के अन्तर्गत रू0 2800 के ग्रेड-पे के वित्तीय स्तरान्तरण के लिए 18 वर्ष की सेवा(8+10वर्ष) पूर्ण करने पर अर्ह हो जाएगा।

(2) यदि उक्त पदधारक को कोई पदोन्नति पुनः प्राप्त नहीं होती है तब उसे तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण पी0बी0-2 में रू0 4200 पर पुनः 10 वर्ष की सेवा अर्थात् कुल 28 वर्ष की सेवा (8+10+10वर्ष) पूर्ण करने पर अर्ह हो जाएगा।

(3) यदि उक्त पदधारक की द्वितीय पदोन्नति पी0बी0-2 ग्रेड-पे रू0 4200 के पद पर 5 वर्ष की और सेवा करने पर हो जाती है उदाहरणार्थ:- 23 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर (8+10+5वर्ष) पूर्ण करने पर उसे तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण 30 वर्ष की सेवा अर्थात् द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य होने के बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रू0 4600 का ग्रेड-पे अनुमन्य होगा।


उक्त परिदृश्य में, उच्चीकरण की अनुमन्यता के पूर्व संगत पे-बैंड में आहरित किये जा रहे वेतन में ग्रेड-पे जोड़कर वेतन में 3 प्रतिशत की वृद्धि



की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसी ग्रेड-पे या उच्चीकृत ग्रेड-पे में नियमित पदोन्नति होने पर पदधारक का कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा और उसे मात्र ग्रेड-पे के अन्तर की धनराशि ही पदोन्नति के समय अनुमन्य होगी।

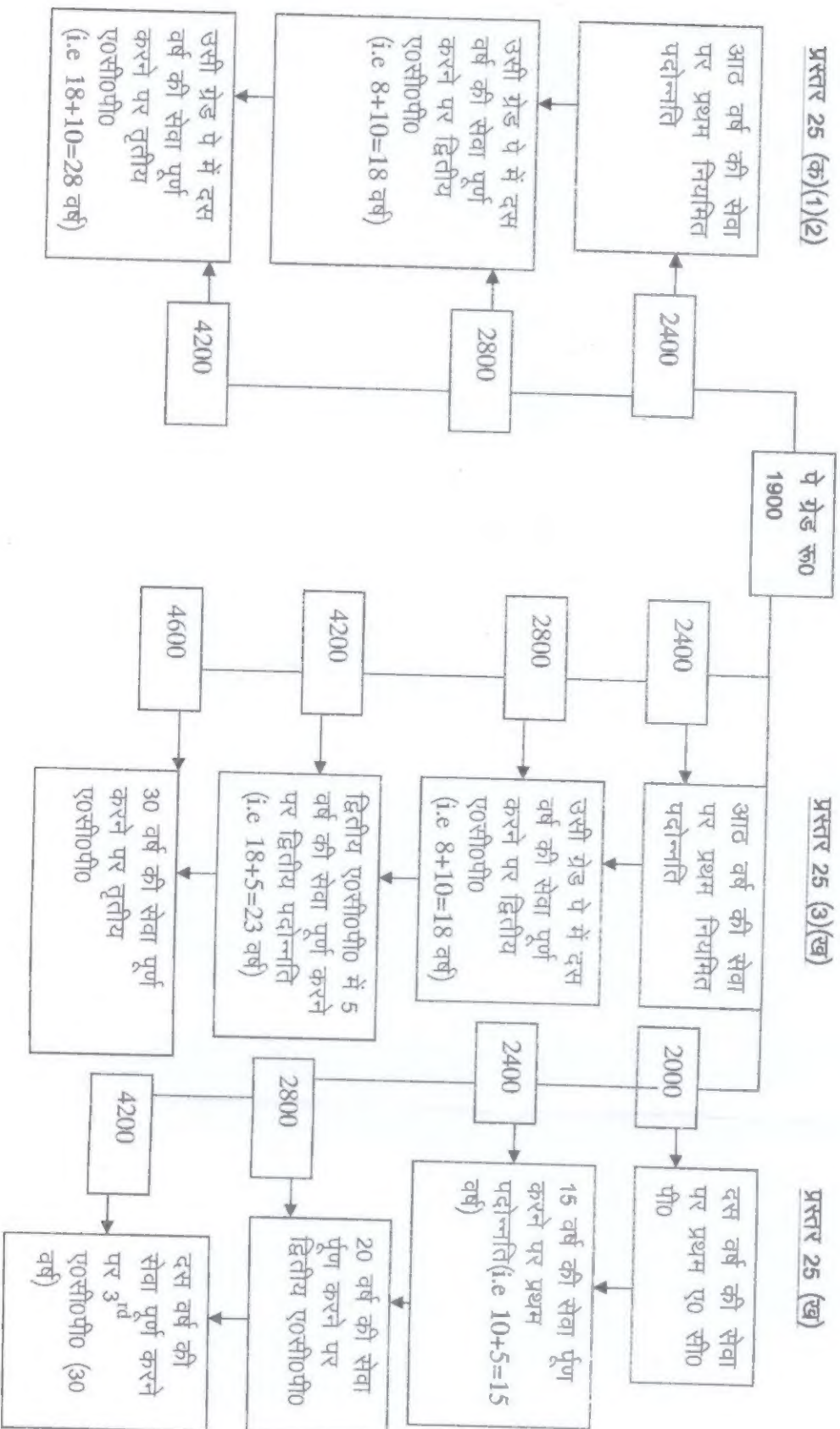
ख-यदि पे-बैण्ड-1 में ग्रेड-पे रू0 1900 के कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिक को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन इसी पे-बैण्ड में रू0 2000 के ग्रेड-पे पर अनुमन्य होने पर 5 वर्ष बाद उसे प्रवर सहायक के पद पर प्रथम नियमित पदोन्नति ग्रेड-पे-रू0 2400 पर उक्त योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन(कार्मिक के द्वारा धारित ग्रेड-पे का अगला ग्रेड पे) 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पी0बी0-1 में ग्रेड-पे रू0 2800 अनुमन्य होगी। उक्त कार्मिक को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उक्त योजनान्तर्गत तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत रू0 4200 का ग्रेड-पे अनुमन्य होगा। लेकिन 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व दो पदोन्नतियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो द्वितीय पदोन्नति के पद के ग्रेड-पे पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, जो भी पूर्व में हो से ही तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा।

ग-यदि सरकारी सेवक को या तो दो नियमित पदोन्नतियाँ या पूर्व समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 7500-12000 तक के वेतनमान के पदधारकों के लिए दिनांक 31-8-2008 तक 24 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय समयमान वेतनमान अनुमन्य हो गया हो, तो उक्त योजना के अन्तर्गत 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अवधि के पूर्व अपने संवर्ग में उसको तृतीय पदोन्नति न प्राप्त हुई हो।

  
(शरद चन्द्र पाण्डे)  
अपर सचिव।



उदाहरण



✓